









**प्रदेशवासियों ने 7 वर्षों में कानून व्यवस्था  
के महत्व को बखूबी अनुभव किया : योगी**

67वीं ऑल इंडिया पुलिस इयूटी मीट के समापन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री

**लखनऊ (हिंस)।** मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेशवासियों ने पिछले 7 वर्षों में कानून व्यवस्था के महत्व को बखूबी अनुभव किया है। प्रदेशवासियों ने प्रदेश के लॉ एंड आर्डर की बेहतर स्थिति और सुरक्षा के माहौल को देखते हुए ही दोबारा इस सरकार को चुना है। आज हर नागरिक के मन में सुरक्षा का विश्वास है। प्रदेश की मजबूत कानून व्यवस्था का ही परिणाम है कि जीआईएस-23 में 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए जबकि 2017 से पहले प्रदेश में निवेश के लिए कोई आना नहीं चाहता था। मुख्यमंत्री ने 67 वर्षों औल ईंडिया पुलिस ड्यूटी मीट के समाप्त समारोह में कहा कि 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नंदें मोदी की मौजूदी में 10 लाख से अधिक निवेश के प्रस्तावों को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए धरातल पर उतारने जा रहे हैं। इससे 35 लाख नौजवानों को सीधे नौकरी मिलेगी, जो यह दर्शाता है कि संकल्प के साथ कानून व्यवस्था को लागू किया जाए तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने स्पारिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं के विजेताओं को ट्रॉफी भी प्रदान की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाने में पुलिस के विभिन्न बलों की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। इतना ही नहीं पब्लिक परसेप्शन तय करने में भी पुलिस बल का अहम रोल है। उन्हें यह परसेप्शन बनाने में काफी चुनौतियों का सामना किया है। इसके लिए उन्हें दोहरी मानसिकता के साथ काम करना पड़ता है। वह असामाजिक और अरास्ट्रीय तत्वों के साथ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपने काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं, जबकि कॉमन मैन के गुहार लगाने पर संवाद स्थापित कर उन्हें न्याय दिलाते हैं। इससे कॉमन मैन के मन में एक नया विश्वास पैदा होता है। साथ ही यह पुलिस बल की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। समारोह में देशभर के विभिन्न बलों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। उनके अपने-अपने अनुभव हैं। उन अनुभवों का लाभ किस रूप में हम ले सकते हैं यह काफी महत्वपूर्ण है। हमारे देश में ज्ञान के आदान-प्रदान की परंपरा वर्षों पुरानी है। लखनऊ से 70 किलोमीटर दूर नौमिशारण्य है, जो हजारों वर्ष पहले ऋषियों के ज्ञान के आदान प्रदान के मंथन का केंद्र था। यहां पर भारत के वैदिक ज्ञान की परंपरा को लिपिबद्ध करने का काम किया गया था। इसमें पूरे देश भर के 88 हजार ऋषि-मुनि शामिल थे। औल ईंडिया पुलिस ड्यूटी मीट इसी धरोहर को आगे बढ़ाता है। योगी ने कहा कि ज्ञान वह नहीं होता है जो पुस्तकों में लिखा होता है, जबकि ज्ञान वह है जो फील्ड की ड्यूटी के दौरान आप अपने अनुभव करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध की बदलती प्रकृति के अनुसार हम सभी को अपने आप को तैयार करना होगा। हम जब अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेज को जनता के सामने शेयर करते हैं तो बहुत कुछ जाने और सीखने को मिलता है। वहीं इस प्रकार की प्रतियोगिताओं और ऐसे प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से बहुत सारी चीजों को देखने और सीखने का अवसर मिलता है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हो चुका है। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अक्सर देश के अंदर की चुनौतियों और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके स्मार्ट पुलिसिंग की बात करते हैं। इस दौरान वह सख्त और सेंसिटिव पुलिस की बात करते हैं। पुलिस बल जब स्मार्ट पुलिसिंग की व्यवस्था से जुड़ता होता है तो वर्तमान की चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सकेगा। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी प्रशांत कुमार समेत कई प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे।

भगवंत मान ने हरियाणा पुलिस के किसानों के आंदोलन के साथ खड़ी है सपा : शिवपाल सीमा पर ड्रोन उड़ाने पर आपत्ति जताई



**चंडीगढ़ ( हिस )** : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा पुलिस के पंजाब की सीमा में ढोन उड़ाने पर आपत्ति जराई है। मान ने केंद्र सरकार और किसान संगठनों के मध्य गुरुवार रात दो बजे तक चली बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, नित्यानंद रॱथ, पीयूष गोयल की मौजूदगी

केंद्र और किसान संगठनों के बीच नहीं हो सकी सहमति, चौथी बैठक कल

शंभू बाड़र पर फायरिंग के विरोध में पंजाब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरियाणा भाजपा कार्यालय घेरा



चंडीगढ़ (हिंस)। हरियाणा व पंजाब की सीमा पर किसान आंदोलन के दौरान पुलिस की फायरिंग से घायल हुए पंजाब के किसानों का समर्थन करते हुए पंजाब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में हरियाणा भाजपा कार्यालय का घेराव किया। पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं व नेताओं ने इसके लिए हरियाणा पुलिस व हरियाणा सरकार को जिम्मेदार

**प्रधानमंत्री 20 को जम्मू-कश्मीर में 3, 161 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास**

**जम्मू (हिंसा)**। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को जम्मू-कश्मीर यात्रा के दौरान 3, 161 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के चुनाव अभियान की औपचारिक शुरूआत भी करेंगे। प्रधानमंत्री जम्मू शहर के एमए स्टेडियम में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। हाल ही में एसटी का दर्जा प्राप्त पहाड़ी समुदाय में इस सार्वजनिक रैली में शामिल होने के लिए विशेष उत्साह देखा जा रहा है। स्टेडियम में दो घंटे के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 3, 161 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और नियुक्ति पत्र भर्ती कांफ्रेंसिंग कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन करेंगे, आगे की प्रतीकात्मकी जाने वाली प्रधानमंत्री शहर में एस्स, फैदेविका कार्यालयों और आईआईएम जम्मू कई प्रमुख सड़कों यात्रा के सुचारू

देंगे और स्टेडियम से एक बीडियो कैमरा के माध्यम से लोगों से बातचीत करेंगे। उत्काकांक्षी जम्मू-श्रीनगर ट्रेन का आंशिक रूप बनिहाल शहर से 48.5 किलोमीटर की दूरी पर बायाकारे गांव में आया है। इसके अलावा उद्घाटन रथोजनाओं में सांबा जिले के विजयपुर गांवी सभा जिले में सभबसे ऊंचा रेलवे पुल, शाहपुर कंडी परियोजना, शाहपुर कंडी परियोजना, जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीजनों में और परियोजनाएँ हैं। प्रधानमंत्री की नियंत्रित चलन को सुनिश्चित करने के लिए

अजमेर ( हिंम )। अजमेर स्थित  
खाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती की  
दरगाह में प्रतिवर्ष की भाँति इस बध  
भी बसंत पंचमी का उत्सव मनाय  
गया। दरगाह के शाही कब्वालों ने हिंम  
पंरपरा के अनुरूप खाजा गरीब नवजात  
की मजार पर सरसों की पौधे के साथ  
पीले पुष्प का गुलदस्ता बसंत के रूप  
में पेश किया। इस दौरान दरगाह के  
शाही कब्वाल पार्टी ने खाजा की शान  
में कलाम पेश किया। कब्वालों ने बसंत  
गाया। कब्वालियां सुनाते हुए मजार  
शरीर तक पहुंचे। दरगाह में बसंत पेश  
करने की परम्परा अमीर खुसरों के

दीवान सैयद जैनुल आबेदीन के पुत्र व  
उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती  
के सानिध्य में दरगाह में पेश बसंत के  
दौरान भारी संख्या में लोग उपस्थित  
रहे। नसीरुद्दीन ने देश में साम्प्रदायिक  
नफरत फैलाने वालों के लिए सूफी  
संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह  
से एक संदेश भी दिया। उन्होंने कहा  
नफरत फैलाने वालों को यह समझना  
होगा कि हम सब पहले भारतीय हैं।  
दिंदू और मुसलमान बाद में हैं। उन्होंने  
कहा कि भारत की सभ्यता की यही  
खूबसूरी है कि हम हर धर्म का त्यौहार  
मिल जुलकर मानते हैं जिस की मिसाल

पहली बार प्रदेश में वक्फ बोर्ड संपत्तियों  
के सर्वे के लिए कर रहा नई कवायद

जयपुर ( हिंस ) । नगर निकाय संस्थाओं की तर्ज पर अपनी सम्पत्तियों का पता लगाकर उर्वे अतिक्रमण मुक्त करने की कवायद में वक्फ बोर्ड जुट गया है । बेशकी मती जमीनों के लिए राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फस अपने सीधे अधीन वाली संपत्तियों का सर्वे करवाने के लिए यह नई कवायद करने जा रहा है । लगातार वक्फ बोर्ड को सम्पत्तियों पर अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही हैं । इसी को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया । बोर्ड की तरफ से अतिक्रमण को ध्वस्त करने के साथ ही कई नोटिस भी जारी किए गए हैं, लेकिन अब संपत्तियों का राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने के लिए जिलों के अनुसार शिविर लगाए जाएंगे । ताकि जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम की तर्ज पर सीधी संपत्ति पर अतिक्रमण और अन्य जानकारी जुटाई जा सके । बोर्ड अद्यक्ष खानू खान बुधवाली के मुताबिक पहले चरण में बोर्ड झुट्टून में दो-तीन दिन का कैप लगाकर अधिकारियों को साथ लेकर इन जमीनों को चिह्नित करने की शुरूआत कर चुका है । बुधवाली ने कहा कि बार-बार कहने के बावजूद लगातार अतिक्रमी आगे बढ़ रहे हैं । हाल ही में कई दरगाह में जमीनों में भूमिकायाओं ने प्लॉटिंग तक कर डाली है । इस बार किसी को बख्खा नहीं जाएगा । इसके लिए यह कदम उठाया जा रहा है । संबंधित निकायों से मदद ली जाएगी । अप्रैल के पहले सप्ताह से यह कवायद शुरू होगी । शासकीय राजपत्र 1989, औंकाफ की पंजी, वर्व राज्य गठन पश्चात वाकिफ द्वारा वक्फ की गई संपत्तियों को शामिल किया जाएगा । इससे सभी जिलों के गांवों, कस्बों में स्थित वक्फ संपत्ति का चिह्नांकन संभव होगा तथा इन संपत्तियों को राजस्व रिकॉर्ड में शामिल किया जा सकेगा । इससे वक्फ की संपत्ति विलुप्त होने से बचेगी । प्रदेशभर में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वेक्षण कार्य में प्रत्येक जिले के जिला प्रशासन के उच्चाधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा ।

**झारखंड प्रशासन**

रांची (हिंस)। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने गुरुवार देर रात अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार कृषि, पशुपालन एवं सहकरिता विभाग के संयुक्त सचिव नवीन कुमार को स्थानांतरित करते हुए देवघर का डीडीसी बनाया गया है। जबकि चतरा के अपर समाहर्ता पवन कुमार मंडल को स्थानांतरित करते हुए चतरा का डीडीसी, गुमला के भूमि सुधार के उपसमाहर्ता सागरी बारल को एसडीओ देवघर, हजारीबाग के चौपारण के अंचल अधिकारी आशीष कुमार मंडल को रामगढ़ के पतरातू का अंचल अधिकारी, साहिबगंज के बरहरवा के अंचल अधिकारी एजाज हुसैन अंसारी को जामताड़ा का कार्यपालक दंडाधिकारी, सरायकेला नगर पंचायत प्रसाद विश्वास पदाधिक सचिव परियोग पद पर विशाला गिरिर्द्धि पूनम व मिथिर सुधार को पदाधिक सुधार को धन बनाया प्रशासन रहेंगी

निक सेवा के कई अवसाद गुप्ता को जमशेदपुर का जिला कल्याण पदाधिकारी, श्रम नियोजन विभाग के संयुक्त सचिव संदीप बक्शी को स्वर्ण रेखा परियोजना जमशेदपुर का संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसी प्रकार वेशाल दीप खलखो को नगर आयुक्त गेरिडीह, संदीप कुमार को बोकारो डीडीसी, मूरम कच्छप को जामताड़ा का अपर समाहर्ता, मथिलेश कुमार चौधरी को गोड्डा का भूमि पुधार विभाग का उपसमाहर्ता, भागीरथ प्रसाद को धनबाद का विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, नरेश रजक को धनबाद का भूमि पुधार विभाग का उपसमाहर्ता, हेमा प्रसाद को धनबाद का अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था बनाया गया है। हेमा को धनबाद का लेखा प्रशासन विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार में होंगी। साथ ही सुदर्शन मुर्मू को रांची का भूमि सुधार एवं रंजीत लोहारा नियोजन कार्यक्रम को रांची का विराजेश कुमार विकास विभाग के कुमार दुबे को संयुक्त सचिव, विभाग का संयुक्त ग्रामीण विकास नागेंद्र पासवान सचिव, महेश कुचिकित्सा शिक्षण संयुक्त सचिव, सचिव कार्यालय संयुक्त सचिव व पदस्थापित किए नंदकिशोर लाल

विभाग को संलग्न लोहरमण्डि को प्रकाश मोहम्मद अब्दुल जनसंघ वेद विजय अलावा स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता सचिव

का संयुक्त सचिव, सुषमा नीलम सोरेन  
कित जनजाति विकास अभिकरण  
का परियोजना निदेशक, संगीता लाल  
वहन विभाग का संयुक्त सचिव, विद्या  
मार को गुमला का लेखा प्रशासन का  
, संजीव कुमार लाल को मन्त्रिमंडल  
नय एवं निगरानी विभाग का उपसचिव,  
कुमार सिंह को पंचायती राज विभाग  
ता पंचायत राज पदाधिकारी, कुमार  
स्वरूप को मन्त्रिमंडल सचिवालय एवं  
विभाग का अवर सचिव, विनय  
तेग्गा को वित्त विभाग का अवर सचिव,  
लियाकत अली को खान विभाग का  
सचिव, पायल राज को सूचना एवं  
के विभाग का अवर सचिव, श्वेता  
श्रम विभाग का अवर सचिव और  
गथ मिश्रा को कृषि विभाग का अवर  
बनाया गया है।

पहली बार प्रदेश में वक्फ बोर्ड संपत्तियों  
के सर्वे के लिए कर रहा नई कवायद

जयपुर ( हिंस )। नगर निकाय संस्थाओं की तर्ज पर अपनी सम्पत्तियों का पता लगाकर उर्वे अतिक्रमण मुक्त करने की कवायद में वक्फ बोर्ड जुट गया है। बेशकी मती जमीनों के लिए राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फस अपने सीधे अधीन वाली संपत्तियों का सर्वे करवाने के लिए यह नई कवायद करने जा रहा है। लगातार वक्फ बोर्ड को सम्पत्तियों पर अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही हैं। इसी को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया। बोर्ड की तरफ से अतिक्रमण को ध्वस्त करने के साथ ही कई नोटिस भी जारी किए गए हैं, लेकिन अब संपत्तियों का राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने के लिए जिलों के अनुसार शिविर लगाए जाएंगे। ताकि जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम की तर्ज पर सीधी संपत्ति पर अतिक्रमण और अन्य जानकारी जुटाई जा सके। बोर्ड अद्यक्ष खानू खान बुधवाली के मुताबिक पहले चरण में बोर्ड झुटनुमें दो-तीन दिन का कैप लगाकर अधिकारियों को साथ लेकर इन जमीनों को चिह्नित करने की शुरूआत कर चुका है। बुधवाली ने कहा कि बार-बार कहने के बावजूद लगातार अतिक्रमी आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में कई दरगाह में जमीनों में भूमिकायाओं ने प्लॉटिंग तक कर डाली है। इस बार किसी को बख्खा नहीं जाएगा। इसके लिए यह कदम उठाया जा रहा है संबंधित निकायों से मदद ली जाएगी। अप्रैल के पहले सप्ताह से यह कवायद शुरू होगी। शासकीय राजपत्र 1989, औंकाफ की पंजी, वर्व राज्य गठन पश्चात वाकिफ द्वारा वक्फ की गई संपत्तियों को शामिल किया जाएगा। इससे सभी जिलों के गांवों, कस्बों में स्थित वक्फ संपत्ति का चिह्नांकन संभव होगा तथा इन संपत्तियों को राजस्व रिकॉर्ड में शामिल किया जा सकेगा। इससे वक्फ की संपत्ति विलुप्त होने से बचेगी। प्रदेशभर में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वेक्षण कार्य में प्रत्येक जिले के जिला प्रशासन के उच्चाधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।





